web: www.nyaysakshi.com || पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल || पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

Govt. Registered Social Justice Union

दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़,बुधवार 05 फरवरी 2020 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-02, अंक- 128

महत्वपूर्ण एवं खास

शाहीन बाग पर हो रही लगातार फायरिंग के बाद बीएसएफ और रैपिड एक्शन फोर्स ने संभाला मोर्चा

नईदिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली के शाहीन बाग में हाल ही में हुई फायरिंग की घटना के बाद अब सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। शाहीन बाग में रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान भी शाहीन बाग पहुंच गए हैं। आपको बताते जाए कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर 52 दिन से धरना जारी है। इसके मद्देनजर सोमवार शाम इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया गया है। वहीं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान भी शाहीन बाग पहुंचे हैं। फोर्स की तैनाती एहतियात के तौर पर की गई है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार जब तक यह कानून वापस नहीं लेती, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। हाल के कुछ दिनों से यहां फायरिंग की गई है। जिसकी दिल्ली पुलिस जांच कर रही है।

निर्भया के दोषियों को जल्द फांसी देने की मांग उठी राज्यसभा में

नईदिल्ली (आरएनएस)। पूरे देश को दहला देने वाले निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्याकांड के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी देने के लिए व्यवस्थात खामियों को दूर करने की मांग करते हुए मंगलवार को राज्यसभा में कहा गया कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। सभापति एम. वेंकैया नायडू ने सदन की चिंताओं से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि कानूनी प्रक्रियाओं में सभी को समान अवसर उपलब्ध होते है लेकिन इनका बेजा फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी संस्थाओं को अपने दायित्व का पालन करना चाहिए। इससे पहले आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने शून्यकाल के दौरान यह मामला उठाते हुए कहा कि निर्भया के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी दी जानी चाहिए।

कोरोना विषाणु के फैलाव पर राज्यसभा में चिंता

नयी दिल्ली (आरएनएस)। राज्यसभा में मंगलवार को कोरोना विषाणु के फैलाव पर गहरी चिंता व्यक्त की गयी और श्वास संबंधी संक्रमित बीमारियों से निपटने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने को कहा गया। भारतीय जनता पार्टी के विकास महात्मे ने सदन में शून्यकाल के दौरान कोरोना विषाणु से संबंधित मामला उठाया और कहा कि श्वास संबंधी बीमारियों के लिए सरकार को विशेष उपाय करने चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से भारत के लोग ऐसी बीमारियों का सामना कर रहे हैं। लगभग प्रतिवर्ष श्वास संबंधी नयी बीमारी सामने आ जाती है। इसलिए सरकार को ऐसी बीमारियों से निपटने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विनय विस्वम ने कोरोना विषाणु से निपटने में केरल सरकार की मदद करने को कहा। उन्होंने कहा कि केरल में इस विषाणु से संक्रमित होने के तीन मामले सामने आ चुके हैं। कांग्रेस के टी सुब्बारामी रेड्डी ने भी कोरोना विषाणु के फैलाव से निपटने के लिए एक पुख्त नीति बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे निपटने के लिए व्यापक स्तर पर जांच की जानी चाहिए।

10 लाख बुजुर्गों को तीर्थयात्रा, स्कूल में देशभक्ति का पाठ

» आप ने जारी किया घोषणा पत्र

नईदिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी ने अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया है. इस दौरान आप नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस मैनिफेस्टो में सीएम अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के भविष्य का विजन शामिल है. इस दौरान आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि आम लोगों की गरिमापूर्ण जीवन के लिए आम आदमी संकल्पित है।

झुग्गियों में रात बिताएंगे भाजपा के 250 सांसद

» पार्टी नेतृत्व का सांसदों को निर्देश » आप के झुग्गी-दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ आर या पार का सियासी जंग लड़ रही भाजपा ने चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में सबकुछ दांव पर लगा दिया है। पार्टी ने 250 सांसदों को अगली तीन रातें झुग्गियों में बिताने का निर्देश दिया है।

पार्टी की योजना इस रणनीति केसहारे झुग्गियों और अनाधिकृत कालोनियों में रहने वाली 40 लाख आबादी को साधने की है। गौरतलब है कि इन कालोनियों में रहने वालों में बड़ी संख्या दलितों की है जिसे आप का कोर वोट बैंक माना जाता है।

पार्टी के रणनीतिकारों का कहना है कि शाहीन बाग सहित अन्य राष्ट्रवादी मुद्दों के सहारे पार्टी ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के साथ अपने कोर वोटरों (30 से 35 फीसदी) को साधने में कामयाबी हासिल कर ली है। चूंकि कांग्रेस की स्थिति कमजोर दिख रही है। ऐसे में पार्टी को अपने वोट प्रतिशत का आंकड़ा 40 फीसदी के पार करना होगा। सांसदों के झुग्गियों और अनाधिकृत कालोनियों में डेरा डालने से पार्टी इस आंकड़े को हासिल करने में कामयाब रहेगी।

दरअसल चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं पर उत्साह नहीं था। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने रणनीति की कमान संभाली और आप के मुफ्त योजनाओं के मुकाबले शाहीन बाग को खड़ा करने केलिए पूरी ताकत लगाई। खुद शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के मैदान में उतरने से पूरा चुनाव आप की मुफ्त योजना बनाम राष्ट्रवाद हो गया है।

पीएम की रैलियां अंत में क्यों?

रणनीतिकारों का कहना है कि पीएम के भाषण का एक वर्ग में व्यापक असर होता है। पार्टी ने जानबूझ कर अंतिम पड़ाव में पीएम की रैलियां करानी सुनिश्चित की, जिससे एकाएक पार्टी के पक्ष में मजबूत माहौल बने। रणनीतिकारों का दावा है कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आर पार का जंग लड़ रही पार्टी के चुनाव प्रचार में पीएम के आने से विकास का भी तड़का लगा है।

स्पीकर ने मुलायम से फैसला करा कर घोषित किया भोजनावकाश

नई दिल्ली (आरएनएस)। लोकसभा में मंगलवार को उस समय अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब विपक्ष ने न सिर्फ भोजनावकाश घोषित करने का विरोध किया, बल्कि इस पर वोटिंग तक की मांग कर डाली। विपक्ष के भोजनावकाश के तीखे विरोध के बाद स्पीकर ने सपा के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव पर फैसला छोड़ा। यादव के भोजन जरूरी है का तर्क देने पर स्पीकर ने भोजनावकाश घोषित कर दिया। दरअसल लोकसभा की कार्यवाही के शुरु होते ही कई विपक्षी दल भाजपा सांसद अनंत हेगड़े की महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी को ले कर आक्रामक भूमिका में थे।

आप आज जारी करेगी घोषणापत्र

» दिल्ली विधानसभा चुनाव

नईदिल्ली (आरएनएस)। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्टीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। घोषणापत्र में महिला सुरक्षा और वायु गुणवत्ता पर नियंत्रण के साथ-साथ अन्य मुद्दे शामिल होंगे।

एक आप नेता ने बताया कि घोषणापत्र में आम आदमी के मुद्दों पर फोकस किया जाएगा। आप ने घोषणापत्र बनाने के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई है। जिसकी अध्यक्ष कालकाजी से उसकी प्रत्याशी आतिशी हैं और दो अन्य सदस्य अजॉय कुमार और जेस्मीन शाह हैं। जहां आतिशी ने ऑक्सफोर्ड से शिक्षा ग्रहण की है और शिक्षा क्षेत्र में सरकार के सुधार कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वहीं अजय कुमार कांग्रेस से लोकसभा सांसद रह चुके हैं और पूर्व आईपीएस अधिकारी भी हैं। जेस्मीन शाह कोलम्बिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स (एसआईपीए) के पूर्व छात्र हैं।

दिल्ली विधानसभा चुनाव के शीर्ष तीन प्रतिद्वंद्वियों में से कांग्रेस और भाजपा अपने-अपने घोषणापत्र पहले ही जारी कर चुके हैं।

स्पीकर ने मुलायम से फैसला करा कर घोषित किया भोजनावकाश

» पहली बार विपक्ष ने की भोजनावकाश पर वोटिंग की मांग

नई दिल्ली (आरएनएस)। लोकसभा में मंगलवार को उस समय अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब विपक्ष ने न सिर्फ भोजनावकाश घोषित करने का विरोध किया, बल्कि इस पर वोटिंग तक की मांग कर डाली। विपक्ष के भोजनावकाश के तीखे विरोध के बाद स्पीकर ने सपा के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव पर फैसला छोड़ा। यादव के भोजन जरूरी है का तर्क देने पर स्पीकर ने भोजनावकाश घोषित कर दिया।

दरअसल लोकसभा की कार्यवाही के शुरु होते ही कई विपक्षी दल भाजपा सांसद अनंत हेगड़े की महात्मा गांधी के खिलाफ

टिप्पणी को ले कर आक्रामक भूमिका में थे। इस कारण एक बार सदन की कार्यवाही स्थगित हुई तो एक बार कांग्रेस समेत कई दलों ने वाकआउट भी किया।

इसके बाद जब भोजनावकाश की बारी आई तो विपक्ष इससे पहले इस विवाद का हल निकालने की मांग करने लगा। स्पीकर चाहते थे कि आमतौर पर एक बजे की तरह मंगलवार को भी भोजनावकाश घोषित हो जाए, मगर विपक्ष विवाद का हल निकाले बिना भोजनावकाश घोषित करने के खिलाफ अड़ गया।

स्थिति तब अजीब हो गई जब एआईएमआईएम केअसादुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में मत विभाजन की मांग रख दी। स्पीकर ने इस मांग को ठुकराते हुए कहा कि सदन में मुलायम सबसे वरिष्ठ हैं। अब वही तय करेंगे कि भोजनावकाश घोषित हो या नहीं। इसकेबाद स्पीकर ने मुलायम से पूछा कि आप बताएं भोजन जरूरी है या नहीं। इस पर मुलायम ने खड़ा हो कर कहा कि भोजन बहुत जरूरी है। फिर स्पीकर ने एक घंटे का भोजनावकाश घोषित कर दिया।

भाजपा के समर्थन में संत समिति ने डेरा डाला

» पूछा गैर वक्फ वाले मस्जिदों के इमामों को वेतन क्यों

» बृहस्पतिवार तक सघन अभियान चलाने की योजना

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवाद के सहारे चुनाव मैदान में डटी भजापा के समर्थन में अब अखिल भारतीय संत समिति ने डेरा डाल दिया है। समिति ने गैर वक्फ वाले मस्जिदों के ईमानों और मुअज्जिमों को वेतन देने के आप सरकार के फैसले को सांप्रदायिक करार दिया है। समिति ने सवाल उठाया है कि फिर इसी आधार पर मंदिरों के पुजरियों को वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा। समिति की योजना चुनाव प्रचार खत्म होने तक राजधानी में डेरा डाले रखने की है।

समिति के महासचिव स्वामी जीतेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि दिल्ली में वक्फ के अंदर आनी वाली मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिमों को वक्फ बोर्ड वेतन देती है। हमें इस पर आपत्ति नहीं है। हमारी आपत्ति केजरीवाल सरकार द्वारा वक्फ के दायरे से बाहर करीब 1500 मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिमों को वेतन देने पर है। कोई भी सरकार संविधान के इतर इस तरह का काम कैसे कर सकती है।

राहुल-प्रियंका आज जंगपुरा और संगम विहार में करेंगे चुनावी रैली को संबोधित

नईदिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। दिल्ली के जंगपुरा और संगम विहार में आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राजौरी गार्डन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अपने सबाब पर है। वहीं कल नरेन्द्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित करके आप और कांग्रेस पर निशाना साधा है।

पीएम मोदी 7 फरवरी को कोकराझार, असम जाएंगे

» बोडो समझौते पर हस्ताक्षर संबंधी समारोह में भाग लेंगे

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 7 फरवरी को बोडो समझौते पर हस्ताक्षर होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए कोकराझार, असम जाएंगे।

कार्यक्रम में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीएडी) जिलों के 4 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। असम सरकार, राज्य की विभिन्नता पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करेगी। स्थानीय समुदाय इस कार्यक्रम में प्रस्तुतियां देंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनवरी में हुए ऐतिहासिक बोडो समझौते के बारे में जनसमुदाय को संबोधित करेंगे। प्रमुख हितधारकों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। समझौते पर 27 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे।

नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट में इस दिन को भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस कहा था। ट्वीट में आगे कहा गया था कि यह समझौता बोडो लोगों के जीवन में बदलाव लाएगा और शांति, सदभावना और मिलजुलकर रहने के एक नई सुबह की शुरूआत होगी।

यह समझौता प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास विजन और पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इससे 5 दशक पुरानी बोडो समस्या का समाधान हुआ है। पीएम ने अपने ट्वीट में कहा कि 'बोडो समझौता कई कारणों से अलग है। जो लोग पहले हथियार के साथ प्रतिरोधी समूहों से जुड़े हुए थे

उर्वशी चूड़ावाला सहित 51 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा

» शरजील इमाम के समर्थन में लगाए थे नारे

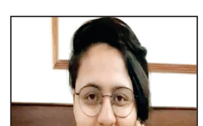

मुंबई (आरएनएस)। पिछले सप्ताह यहां आजाद मैदान में एलजीबीटीक्यू कार्यक्रम में जेएनयू छात्र शरजील इमाम के समर्थन में कथित रूप से च्राष्ट विरोधी नारे लगाने को लेकर मुम्बई पुलिस ने सोमवार को सामाजिक कार्यकर्ता उर्वशी चूड़ावाला पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया।चूड़ावाला के अलावा 50 अन्य पर भी भारतीय दंड संहिता की धारा-124 ए (देशद्रोह), 153 बी (राष्टीय अखंडता के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण बयान), 505 (लोगों को उकसाने के लिए दिया गया बयान), 34 (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।इससे पहले सोशल मीडिया पर एक एक वीडियो सामने आया था जिसमें चूड़ावाला एक फरवरी को एलजीबीटीक्यू कार्यक्रम में कथित रूप से नारे लगाते दिखे थे।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने दो फरवरी को इस संबंध में एक शिकायत दर्ज करायी थी। गौरतलब है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने को लेकर इमाम को बिहार के जहानाबाद से 28 जनवरी को गिरफ्तार किया।

कुपवाड़ा में पाक ने किया युद्धविराम का उल्लंघन, एक नागरिक की मौत, 4 घायल

श्रीनगर (आरएनएस)। उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के सीमावर्ती शहर करनाह में पाकिस्तान ने फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए अंधाधुंध गोलीबारी की जिसमें एक नागरिक की मौत हो गयी और अन्य चार घायल हो गये। आधिकारिक सूत्रों ने बतया कि पाकिस्तानी सेना ने पिछले 24 घंटे के दौरान करनाह के इलाकों में बिना किसी उकसावे के भारतीय सेना की अग्रिक चौकियों और नागरिक इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी की है। पिछले 48 घंटों में पाकिस्तानी की सेना की संघर्ष विराम के उल्लंघन की यह चौथी घटना है। गोलबारी में कई आवासीय घरों को भी नुकसान पहुंचा है।

गांधी विरोधी टिप्पणी करने वाले हेगड़े ने भाजपा को उलझाया

» माफी मांगने से इंकार संसदीय दल की बैठक से भी किया किनारा

नई दिल्ली (आरएनएस)। महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले सांसद अनंत हेगड़े ने भाजपा और मोदी सरकार को बुरी तरह से उलझा दिया है। पार्टी की योजना लोकसभा में हेगड़े से माफी मंगवा कर विपक्ष की नाराजगी खत्म करने की थी। हालांकि हेगड़े ने न सिर्फ माफी मांगने से इंकार किया बल्कि मंगलवार को पार्टी की संसदीय दल की बैठक के साथ लोकसभा की कार्रवाई से भी किनारा कर

लिया। इसक बाद नाराज नेतृत्व ने हेगड़े का मामला पार्टी की अनुशासन समिति को भेज दिया है।

सूत्रों के मुताबिक सोमवार को पार्टी के एक शीर्ष नेता ने हेगड़े को फोन पर कड़ी फटकार लगाते हुए मंगलवार को लोकसभा में आ कर माफी मांगने का निर्देश दिया था। इसके बाद मंगलवार को जब हेगड़े संसदीय दल की बैठक में नहीं पहुंचे तब पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक में पार्टी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील को हेगड़े के निवास पर भेजा। मगर हेगड़े ने कटील से मुलाकात करने से मना कर दिया। इसके बाद पाटी नेतृत्व ने हेगड़े से संबंधित मामले को पार्टी की अनुशासन समिति को भेजने का फैसला किया।

राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी लाने का नहीं हुआ निर्णय

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनआरसी) पर देश भर में हो रहे व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच सरकार ने कहा है कि अभी एनआरसी को राष्ट्रीय स्तर पर लाने का कोई निर्णय नहीं हुआ है।

इसके अलावा सरकार ने यह भी साफ किया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करने के दौरान किसी तरह के दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। यहां तक कि आधार कार्ड नंबर तक देना वैकल्पिक होगा। लोकसभा में सांसद चंदन सिंह, नामा नागेश्वर राव और मनीष तिवारी के सवालों जवाब में गृह

राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस आशय की जानकारी दी। यह सवाल प्रश्नकाल के मौखिक प्रश्नों की सूची में शामिल था। हालांकि विपक्ष के हंगामे के कारण प्रश्नकाल स्थगित हो गया। गृह राज्य मंत्री ने लिखित जवाब में कहा कि एनपीआर अपडेटशन के दौरान हर परिवार और व्यक्ति की जानकारी ली जाएगी। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। इस दौरान किसी तरह का दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान ऐसा कोई वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा जिससे किसी की नागरिकता पर सवाल खड़ा हो। अगर कोई व्यक्ति आधार कार्ड नंबर भी नहीं देना चाहे तो वह इसके लिए स्वतंत्र है। राय ने कहा कि इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले केंद्र सरकार राज्य सरकारों से बात भी करेगी। गौरतलब है कि एनपीआर की प्रक्रिया एक अप्रैल से शुरू होगी। इसे जनगणना का पहला चरण माना जा रहा है।

गौरतलब है कि संसद के दोनों सदनों में सीएए से जुड़े बिल पर चर्चा के जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर में एनआरसी लागू करने की घोषणा की थी। इसके बाद सीएए के विरोध में शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि विपक्ष उस एनआरसी का विरोध कर रहा है जिस पर सरकार में किसी भी स्तर पर चर्चा तक नहीं हुई है। इस पर विपक्ष ने गृह मंत्री के संसद में दिए बयान का हवाला दिया था।